



## नीतिआयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक

### प्रलिस के लयि:

नीतिआयोग, वकिसति भारत @2047, शून्य गरीबी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, पराकृतक कृषि, साइबर सुरक्षा, सहकारी संघवाद, SDG इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मशिन ।

### मेन्स के लयि:

सहकारी संघवाद में नीतिआयोग की भूमिका, संवधानेतर नकिय

स्रोत: पी.आई.बी

## चर्चा में क्यो?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीतिआयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को वकिसति भारत @2047" थीम पर चर्चा करने के लयि बुलाया गया, जसिका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक वकिसति राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापति करना है ।

## बैठक के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का वज़िन/दृष्टिकोण: भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP लक्ष्य के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है । यह महत्त्वाकांक्षा देश के सतत आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा पर ध्यान केंद्रति करने को उजागर करती है ।
- वर्ष 2047 हेतु राज्य का दृष्टिकोण: बैठक में प्रत्येक राज्य और ज़िले को वकिसति भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखति करते हुए वर्ष 2047 के लयि अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहति कयिा गया ।
  - राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कविकिसति भारत के लयि वकिसति राज्य महत्त्वपूर्ण हैं ।
- शून्य गरीबी लक्ष्य: बैठक से एक महत्त्वपूर्ण नषिकर्ष यह निकला क वियक्तगित स्तर पर गरीबी उन्मूलन पर ज़ोर दयिा गया । 'शून्य गरीबी' वाले गाँवों की अवधारणा पर चर्चा की गई जसिका उद्देश्य ज़मीनी स्तर से समग्र विकास करना है ।
- बुनियादी ढाँचा और नविश: प्रधानमंत्री ने नविश आकर्षति करने के लयि बुनियादी ढाँचे, कानून और व्यवस्था तथा सुशासन के महत्त्व पर ज़ोर दयिा ।
  - राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से नगिरानी करते हुए, नविशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लयि राज्यों को प्रोत्साहति करने हेतु एक 'नविश-अनुकूल चार्टर' प्रस्तावति कयिा गया ।
- शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं को रोज़गार के लयि तैयार करने हेतु उनके कौशल पर ज़ोर दयिा गया, जसिसे वैश्विक कुशल संसाधन केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके ।
- कृषि उत्पादकता और पराकृतक कृषि: उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में वविधिता लाने तथा पराकृतक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, ताका भूदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच बनाई जा सके ।
- जीवन की सुगमता/ईज़ ऑफ लयिगि: मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सफिरशियों पर वचिार कयिा गया, जसिमें पेयजल, वदियुत, स्वास्थ्य, सकूली शिक्षा और भूमि/संपत्ति प्रबंधन जैसे 5 प्रमुख वषियों पर ध्यान केंद्रति कयिा गया ।
  - प्रधानमंत्री ने राज्यों को भवषिय में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से नपिटने हेतु जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएँ शुरू करने के लयि प्रोत्साहति कयिा ।
  - प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता नरिमाण का कार्य करने को कहा तथा इसके लयि उन्हें क्षमता नरिमाण आयोग के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहति कयिा ।
  - प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लयि राज्य स्तर पर नदी गर्डों के नरिमाण को प्रोत्साहति कयिा ।
- शासन में साइबर सुरक्षा और AI: शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु AI का लाभ उठाने को भवषिय की तत्परता के लयि महत्त्वपूर्ण कषेत्रों के रूप में रेखांकति कयिा गया ।

## नोट:

- 'जीवन की सुगमता' की व्यापक थीम के तहत, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नमिनलखिति पाँच प्रमुख वषियों पर अनुशासार्ँ की गईः
  - पेयजल: पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता
  - वदियुत: गुणवत्ता, दकषता और वशिवसनीयता
  - सवासुथयः सुगम्यता, सामरुथय और देखभाल की गुणवत्ता
  - सकूली शकषिः पहुँच और गुणवत्ता
  - भूमा और संपत्तः सुगम्यता, डजिटिलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन

## नीतऱआयोग की शासी परषिद क्या है?

- परचियः
  - शासी परषिद एक प्रमुख नकऱय है जसकऱ कारुय वकऱस को आकार देने में राजुयों की सकरुयि भागीदारी के साथ राष्टुरीय प्रऱथमकऱताओं और रणनीतऱियों का साझा दृषुकऱोण वकऱसऱि करऱना है ।
  - सहकारी संघवाद के उददेशुयों को मूरुत रूड देने वाली शासी परषिद, राष्टुरीय वकऱस एजेंडे के कारुयऱनुवयन में तेजुी लऱने के लऱयऱ अंतर-कषेतरुीय, अंतर-वभागीय और संघीय मुदुदों पर चरुचा करने हेतु एक मंच प्रसुतुत करुती है ।
- सदसुयः
  - भारत के प्रधऱनमंतुरी (अधुयकष)
  - मुखुयमंतुरी (वधऱनसभा वाले राजुय और केंदुरशासऱि प्रदेश)
  - अनुय केंदुरशासऱि प्रदेशों के उपराजुयपाल
  - पदेन सदसुय
  - नीतऱआयोग के उपाधुयकष
  - नीतऱआयोग के पूरणकऱलकऱ सदसुय
  - वशेष आमंतुरऱि सदसुय
- कारुयः
  - शासी परषिद सचऱवलऱय (GCS) शासी परषिद की बैठकों का समनुवय करुता है ।
    - यह नीतऱआयोग के सभी कारुयकषेतरुों, प्रभागों और इकऱइयुओं की गतऱवधऱयुओं का समनुवय भी करुता है ।
  - GCS संसद में परचऱलन के लऱयऱ नीतऱआयोग की वऱरुषकऱि रऱडुररुट से संबंघऱि मामलों के समनुवय हेतु नुडल प्रभाग के रूड में कारुय करुता है ।
  - यह प्रभाग संसदुीय प्रशऱनों, सुथऱयी समतऱि के मामलों, RTI प्रशऱनों, GCS से संबंघऱि केंदुरीकृत लुक शकऱयत नऱवारण और नगऱरऱनी प्रणऱली (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System- CPGRAMS) शकऱयतुओं को भी संभऱलता है ।

## नीतऱआयोग क्या है?

- परचियः
  - युजऱनऱ आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नऱ संसुथऱन नीतऱआयोग दऱरऱ प्रतऱसुथऱपतऱ कऱयऱ गऱया थऱ, जसऱमें 'सहकारी संघवाद' की भावऱनऱा को प्रतऱधऱवनतऱि करुते हुऱए 'अधकऱतम शासन, नुनूतम सरकरऱर' की परकऱलपऱनऱा के लऱयऱ 'बुुऑम-अप' दृषुकऱोण पर जुरुर दऱयऱ गऱया थऱ ।
  - इसमें दुु हब हैंः
    - टीम इंडऱयऱ हब- यह राजुयुओं और केंदुर के बीच इंटरफेस का कारुय करुता है ।
    - जुजऱऱन और नवऱनुमेष हब- यह नीतऱआयोग के थकऱ-टैक के रूड में कारुय करुता है ।
- पहलः
  - SDG इंडऱयऱ इंडेकस
  - समगुर जल प्रबंघन सुचकऱंक
  - अटल नऱवऱचार मशऱन
  - SATH प्रुजेकट
  - आकऱकषी जुरऱलऱ कारुयकरम
  - सकूल शकषिऱ गुणवत्तऱ सुचकऱंक
  - जुरऱलऱ असपतऱल सुचकऱंक
  - सऱवऱसुथय सुचकऱंक
  - कृषऱऱवऱपऱणन और कसऱऱन हतऱषी सुधऱर सुचकऱंक
  - भऱरत नऱवऱचार सुचकऱंक
  - वुमन टुरऱंसफुुऑरमऱगऱ इंडऱयऱ अऱवऱरडुस
  - सुशासन सुचकऱंक

**दृष्टि मैनस प्रश्न:**

**प्रश्न.** भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीतिआयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन की गुणवत्ता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है?

**UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न**

**??????????:**

**प्रश्न.** अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मशिन किसके अधीन स्थापति कथिया गया है? (2019)

- (a) वजिज्ञान और प्रौद्योगिकी वभिग
- (b) श्रम और रोजगार मंत्रालय
- (c) नीतिआयोग
- (d) कौशल वकिस एवं उद्यमति मंत्रालय

**उत्तर: (c)**

**प्रश्न.** भारत सरकार ने नीति(NITI) आयोग की स्थापना नमिनलखिति में से किसका स्थान लेने के लिये की है? (2015)

- (a) राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग
- (b) वक्ति आयोग
- (c) वधिआयोग
- (d) योजना आयोग

**उत्तर: (d)**

**??????????:**

**प्रश्न.** भारत में 'महत्त्वाकांक्षी ज़िलों के कायाकल्प' के लिये मूल रणनीतियों का उल्लेख कीजिये और इसकी सफलता के लिये, अभिसरण, सहयोग व प्रतस्पर्द्धा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिये। (2018)